



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27052020-219588
CG-DL-E-27052020-219588

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 132]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 27, 2020/ज्येष्ठ 6, 1942

No. 132]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 27, 2020/JYAISTHA 6, 1942

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरूआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 मई, 2020

मामला संख्या: एडीडी- (ओ आई) 17/2020

विषय: चीन जन.गण., कोरिया गण. और यू एस ए से “रबड़ कैमिकल पीएक्स-13” के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरूआत।

फा. सं. 06/20/2020-डीजीटीआर.—1. मै. एनओसीआईएल लिमिटेड (जिन्हें यहां आगे “आवेदक” भी कहा गया है) ने समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) और सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षतिनिर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियमावली भी कहा गया है) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन दायर किया है जिसमें चीन जन.गण., कोरिया गण. और यू एस ए (जिन्हें आगे संबद्ध देश भी कहा गया है) से “रबड़ कैमिकल पीएक्स-13” (जिसे आगे संबद्ध वस्तु या विचाराधीन उत्पाद या पीयूसी भी कहा गया है) के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरूआत करने का अनुरोध किया गया है।

2. आवेदक ने आरोप लगाया है कि चीन जन.गण., कोरिया गण. और यू एस ए से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति हो रही है और इन देशों से संबद्ध वस्तु के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लागू करने का अनुरोध किया है।

विचाराधीन उत्पाद

3. विचाराधीन उत्पाद “रबड़ कैमिकल्स पीएक्स-13” (जिसे यहां आगे “पीएक्स-13” भी कहा गया है) है जिसे 6पीपीडी, एंटीऑक्सीडेंट 6पीपीडी, कुमानोक्स 13, सेंटोफ्लैक्स 6पीपीडी, सिरनटॉक्स 6पीपीडी, वूल्कानॉक्स 4020, एंटीऑक्सीडेंट 4020, डुसान्टॉक्स 6पीपीडी, एंटेज 6सी, एन-1, 3-डीमेथाइलब्यूटाइल)- एन-फिनाइल-पी-फिनाइलीनडाइमीन आदि के रूप में भी जाना जाता है।
4. पीएक्स-13 एक एल्काइल-एराइल-पीपीडी एंटीडीग्रेटेंट होता है जिसका रबड़ उद्योग के टायर और गैर-टायर क्षेत्र में व्यापक रूप से प्रयोग होता है। पीएक्स-13 डी-ग्रेडेटिव शक्तियों जैसे ओजोन (स्थिर तथा गतिशील), फ्लैक्स क्रेकिंग और फटींग, ऑक्सीडेटिव हीट ऐजिंग, मेटल ऑयन केटेलाइज्ड ऑक्सीडेटिव ऐजिंग, यूवी लाइट और वैदरिंग के विरुद्ध रबड़ बलकेनीजेट के लिए उत्कृष्ट प्रतिरोध प्रदान करता है। इसका प्रयोग रबड़ उत्पाद के वांछित जीवन चक्र को प्राप्त करने के लिए विभिन्न रबड़ उत्पादों के विनिर्माण में प्रयुक्त प्राकृतिक रबड़, कृत्रिम रबड़ (एसबीआर, ब्यूटाडिन रबड़, नाइट्राइल रबड़, कार्बोक्सीलेटेड रबड़) और अन्य कृत्रिम रबड़ आधारित यौगिकों के उपचार में एंटी ऑक्सीडेंट के रूप में किया जाता है। पीएक्स-13 का विनिर्माण 4एडीपीए और एमआईबीके के रिडेक्टिव एल्कीलेशन द्वारा किया जाता है।
5. इस उत्पाद को सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के अध्याय 38 के अधीन टैरिफ सीमाशुल्क वर्गीकरण 3812 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। तथापि, पहली अनुसूची के अध्याय-29 के अंतर्गत भी विचाराधीन उत्पाद के आयात होते हैं। सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

समान वस्तु

6. आवेदक ने दावा किया है कि संबद्ध देशों से निर्यातित संबद्ध वस्तु और घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध वस्तु अनिवार्य उत्पाद विशेषताओं जैसे भौतिक और रासायनिक विशेषताएं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और प्रयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण की दृष्टि से तुलनीय हैं। उपभोक्ता इनका एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग करते हैं। आवेदक ने यह भी दावा किया है कि ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं इसलिए नियमावली के अंतर्गत इन्हें समान वस्तु माना जाना चाहिए। अतः वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ भारत में आवेदक द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु को संबद्ध देशों से आयातित की जा रही संबद्ध वस्तु के समान वस्तु माना जा रहा है।

घरेलू उद्योग

7. यह आवेदन मै. एनओसीआईएल लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। आवेदक ने दावा किया है कि उन्होंने न तो संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु का आयात किया है और न ही वे संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तु के किसी निर्यातक अथवा उत्पादक या भारत में पीयूसी के किसी आयातक से संबंधित हैं। रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना पर विचार करते हुए आवेदक का भारतीय उत्पादन में “एक बड़ा हिस्सा” बनता है। उपर्युक्त के मद्देनजर और आवश्यक जांच के बाद प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक संबंधित नियमावली के नियम 2(ख) के अनुसार पात्र घरेलू उद्योग हैं और आवेदन नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार स्थिति संबंधी मापदंडों को पूरा करता है।

कथित पाटन के लिए आधार

क. चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य

8. आवेदक ने दावा किया है कि चीन जन.गण को गैर बाजार अर्थव्यवस्था माना जाना चाहिए और सामान्य मूल्य का निर्धारण नियमावली के अनुबंध-1 के पैराग्राफ-7 के अनुसार किया जाना चाहिए। आवेदक ने नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 8(2) का उल्लेख किया है और यह बताया है कि चीन के उत्पादकों को यह दर्शाने का निर्देश दिया जाना चाहिए कि नियमावली के अनुबंध 1 के पैरा 8 (3) के अनुसार संबद्ध वस्तु का उत्पादन करने वाले उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था की दशाएं मौजूद हैं। आवेदक ने दावा किया है कि चीन के लिए सामान्य मूल्य को नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 और 8 के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए। उचित बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश ने विचाराधीन उत्पाद की कीमतें या परिकलित मूल्य या भारत सहित अन्य देशों को ऐसे तीसरे देश से कीमतें आवेदक द्वारा न तो उपलब्ध कराई गई हैं और न ही किसी सार्वजनिक स्रोत से प्राधिकारी के पास ऐसी सूचना उपलब्ध है। इस प्रकार, सामान्य मूल्य को भारत में प्रदत्त या देय कीमत को लाभ को शामिल करने के लिए विधिवत रूप से समायोजित करके निर्धारित किया गया है, जिसे बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय और तर्कसंगत लाभ को जोड़ने के बाद भारत में उत्पादन लागत पर विचार करते हुए निर्धारित किया गया है।

ख. यूएसए तथा कोरिया के लिए सामान्य मूल्य

9. आवेदक ने दावा किया है कि यूएसए और कोरिया में कीमत से संबंधित आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। आवेदक ने समुचित तीसरे देश के संबंध में सूचना प्रदान नहीं की है। यह सूचना किसी सार्वजनिक स्रोत से भी प्राधिकारी के पास उपलब्ध नहीं है। यूएसए और कोरिया का सामान्य मूल्य इन देशों में उत्पादन लागत से सर्वोत्तम अनुमानों में संबंधित बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय तथा तर्कसंगत लाभ को जोड़कर उनके आधार पर किया है।

ग. निर्यात कीमत

10. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों के लिए संबद्ध वस्तु की निर्यात कीमत का परिकलन वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डी जी सी आई एंड एस) से प्राप्त सौदावार आयात आंकड़ों के आधार पर किया है। समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, पत्तन व्यय, बैंक प्रभार, कमीशन, अंतरदेशीय मालभाड़ा व्यय और चीन जन. गण. के मामले में वैट के लिए समायोजन किए गए हैं।

घ. पाटन मार्जिन

11. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की कारखाना द्वार स्तर पर तुलना की गई है जिससे प्रथम दृष्टया संबद्ध देशों से पीयूसी के संबंध में पाटन मार्जिन के न्यूनतम सीमा से अधिक स्तरों पर होने और अत्यधिक होने का पता चलता है। इस बात के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं कि संबद्ध देशों से निर्यातकों द्वारा भारतीय बाजार में संबद्ध देशों से पी यू सी का पाटन किया जा रहा है।

क्षति और कारणात्मक संबंध के साक्ष्य

12. आवेदक द्वारा प्रस्तुत सूचना पर घरेलू उद्योग को हुई क्षति के आकलन हेतु विचार किया गया है। आवेदक ने समग्र रूप से और भारत में उत्पादन और खपत की दृष्टि से पाटित आयातों की बढ़ी हुई मात्रा, कीमत कटौती और घरेलू उद्योग पर कीमत ह्रासकारी प्रभाव के रूप में जांच अवधि के दौरान पाटित आयातों के कथित पाटन के परिणामस्वरूप क्षति के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। आवेदक ने दावा किया है कि उनका कार्य निष्पादन घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत और क्षतिरहित कीमत से कम कीमत पर संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद के आयातों में वृद्धि के परिणामस्वरूप उत्पादन, क्षमता उपयोग, घरेलू बिक्री मात्राओं, बाजार हिस्सा, लाभप्रदता, नकद प्रवाह और नियोजित पूंजी पर आय की दृष्टि से बुरी तरह प्रभावित हुआ है। आवेदक ने यह भी दावा किया है कि संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तु की भारी क्षमता तथा घरेलू बिक्री कीमतों पर आयात कीमतों से ह्रासकारी और न्यूनकारी प्रभाव के मद्देनजर घरेलू उद्योग को आगे और क्षति होने का खतरा है। इस बात के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है।

पाटनरोधी जांच की शुरुआत

13. घरेलू उद्योग के द्वारा या उसकी ओर विधिवत रूप से साक्ष्यांकित लिखित आवेदन के आधार पर और घरेलू उद्योग द्वारा संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के पाटन, घरेलू उद्योग को क्षति और कथित पाटन और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के बारे में घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर स्वयं को संतुष्ट करने के बाद और नियमावली के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9A के अनुसार प्राधिकारी एतद्वारा संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के संबंध में किसी कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण करने और पाटनरोधी शुल्क की ऐसी राशि की सिफारिश करने जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगी, जांच की शुरुआत करते हैं।

संबद्ध देश

14. इस जांच में संबद्ध देश चीन जन गण, कोरिया गणराज्य और यू एस ए हैं।

जांच की अवधि (पीओआई)

15. वर्तमान जांच के लिए जांच अवधि (पीओआई) 1 अप्रैल, 2019 से 31 मार्च, 2020 (12 महीने) की है, क्षति जांच अवधि में 1 अप्रैल, 2016 - 31 मार्च, 2017, 1 अप्रैल, 2017-31 मार्च, 2018, 1 अप्रैल, 2018-31 मार्च, 2019 और पी ओआई की अवधियां शामिल हैं।

प्रक्रिया

16. नियमावली के नियम 6 में यथाप्रदत्त सिद्धांतों का वर्तमान जांच में पालन किया जाएगा।

सूचना प्रस्तुत करना

17. कोविड-19 महामारी से उत्पन्न विशेष परिस्थितियों के मद्देजर निर्दिष्ट प्राधिकारी को समस्त पत्र ई-मेल पत्तों adg13-dgtr@gov.in तथा adv12-dgtr@gov.in पर ई-मेल के माध्यम से भेजे जाने चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का वर्णनात्मक भाग खोजने योग्य पीडीएफ/ एम एस वर्ल्ड फार्मेट में हो और आंकड़ों की फाइलें एमएस एक्सेल फार्मेट में हों।
18. ज्ञात निर्यातकों, भारत में उनके दूतावास के जरिए उनकी सरकारों, भारत में संबद्ध वस्तु से संबंधित समझे जाने वाले आयातकों और प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग को नीचे निर्धारित की गई समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र में एवं ढंग से समस्त संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है।
19. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी उपर्युक्त पैरा 17 में उल्लिखित ई-मेल पते पर नीचे दी गई समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र और ढंग से इस जांच से संगत अपने अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है।
20. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराए जाने के लिए उसका एक अगोपनीय अंश प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

समय-सीमा

21. वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार सूचना की प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों के भीतर ईमेल पत्तों adg13-dgtr@gov.in तथा adv12-dgtr@gov.in पर ई-मेल के माध्यम से निर्दिष्ट प्राधिकारी को भेजी जानी चाहिए। तथापि, यह नोट किया जाए कि उक्त नियम के स्पष्टीकरण के अनुसार सूचना और अन्य दस्तावेज मंगाने वाले नोटिस को निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा उसे भेजे जाने की तारीख या निर्यातक देश के उचित राजनयिक प्रतिनिधि को दिए जाने की तारीख से एक सप्ताह के भीतर प्राप्त हुआ माना जाएगा। यदि विहित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो प्राधिकारी नियमावली के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।
22. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना देने और उपर्युक्त समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह दी जाती है।

गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

23. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने या गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार को नियमावली के नियम 7(2) और इस संबंध में जारी की गई व्यापार सूचनाओं के अनुसार उसका अगोपनीय अंश भी साथ में प्रस्तुत करना अपेक्षित है। उपर्युक्त का पालन न करने पर उत्तर/अनुरोध को अस्वीकृत किया जा सकता है।
24. प्रश्नावली के उत्तर सहित प्राधिकारी के समक्ष कोई अनुरोध (उससे संलग्न परिशिष्ट/अनुबंध सहित) प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों के लिए गोपनीय और अगोपनीय अंश अलग-अलग प्रस्तुत करना अपेक्षित है।
25. "गोपनीय "या" अगोपनीय "अनुरोधों पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर" गोपनीय "या" अगोपनीय "अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोध का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।
26. गोपनीय पाठ में ऐसी समस्त सूचना होगी जो स्वाभाविक रूप से गोपनीय है और/अथवा ऐसी अन्य सूचना जिसके ऐसी सूचना के प्रदाता द्वारा गोपनीय होने का दावा किया गया है। स्वाभाविक रूप से गोपनीय होने का दावा की गई सूचना या अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा की गई सूचना के संबंध में सूचना प्रदाता को प्रदत्त सूचना के साथ ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत करना होगा कि उस सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है।
27. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई (यदि सूचीबद्ध करना व्यवहार्य न हो) और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की विषय वस्तु को तर्कसंगत ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांशीकरण क्यों संभव नहीं है।
28. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।
29. सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।
30. प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार कर लेने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

31. नियमावली के नियम 6 (7) के अनुसार कोई हितबद्ध पक्षकार उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है जिसमें अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतरण रखे गए हैं। इलैक्ट्रॉनिक रूप में सार्वजनिक फाइल को रखे जाने के तौर तरीके तैयार किए जा रहे हैं।

असहयोग

32. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

भूपिन्दर एस. भल्ला, अपर सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)****INITIATION NOTIFICATION**

New Delhi, the 27th May 2020

Case No. ADD-OI-17/2020**Subject: Initiation of Anti-Dumping Investigation concerning imports of “Rubber Chemical PX-13” from China PR, Korea RP and USA.**

F. No. 06/20/2020-DGTR.—1.M/s NOCIL Limited (hereinafter also referred to as Applicant) has filed an application seeking initiation of anti-dumping investigation concerning imports of “Rubber Chemical PX-13” (hereinafter also referred to as “subject goods” or “product under consideration” or “PUC”) from China PR, Korea RP and USA (also referred to as “subject countries”) before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the “Authority”) in accordance with Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (herein also referred to as the “Act”) and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Antidumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (hereinafter also referred to as the “Rules”).

2. The Applicant has alleged that material injury to the Domestic Industry is being caused due to dumped imports from China PR, Korea RP, and USA, and has requested for imposition of anti- dumping duty on the imports of the subject goods from these countries.

Product under Consideration (PUC)

3. The product under consideration is “Rubber Chemicals PX-13” (hereinafter also referred to as PX-13) also known as 6PPD, Antioxidant 6PPD, Kumanox 13, Santoflex 6PPD, Sirantox 6PPD, Vulkanox 4020, Antioxidant 4020, Dussantox 6PPD, Antage 6C, N-1,3-Dimethylbutyl)-N'-Phenyl-P-Phenylenediamine, etc.
4. PX-13 is an alkyl-aryl-PPD antidegradant most widely used in the tyre and non-tyre sector of the rubber industry. PX-13 offers excellent resistance to rubber vulcanizates against degradative forces such as ozone (static as well as dynamic), flex-cracking and fatigue, oxidative heat ageing, metal-ion catalyzed oxidative ageing, UV light and weathering. It is used as antioxidants in treating natural rubber, synthetic rubber (SBR, Butadiene Rubber, Nitrile Rubber, Carboxylated Rubber) and other synthetic rubber-based compounds used for manufacture of various rubber products to achieve the desired life cycle of the rubber product. PX-13 is manufactured by reductive alkylation of 4ADPA and MIBK.
5. The product is classified under the Chapter 38 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) under the tariff custom classification 3812. However, there are also imports for the product under consideration under the Chapter 29 of the First Schedule. The customs classification is only indicative and is not binding on the scope of the product under consideration.

Like Article

6. The Applicant has claimed that there is no known difference between the subject goods exported from the subject countries and that produced by the domestic industry. Subject goods produced by the domestic industry and imported from the subject countries are comparable in terms of essential product characteristics such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. Consumers use the two interchangeably. The Applicant has further claimed that the two are technically and commercially substitutable and, hence, should be treated as like article under the Rules. Therefore, for the purpose of the present investigation, the subject goods produced by the Applicant in India are being treated as ‘Like Article’ to the subject goods being imported from the subject countries.

Domestic Industry & Standing

7. The Application has been filed by M/s NOCIL Limited. The Applicant has claimed that they have neither imported the subject goods from the subject countries nor are related to any exporter or producer of subject goods in the subject countries or any importer of the PUC in India. Considering the information on record, the Applicant accounts for a major proportion of the Indian production. In view of the above and after due examination, the Authority notes that the Applicant constitutes eligible domestic industry in terms of Rule 2 (b), and the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5(3) of the Rules supra.

Basis of Alleged Dumping**a. Normal Value for China PR**

8. The Applicant has claimed that China PR should be treated as a non-market economy and the normal value should be determined in terms of paragraph-7 of Annexure I of the Rules. The Applicant has cited Para 8(2) of Annexure I of the Rules and has stated that the Chinese producers should be directed to demonstrate that

market economy conditions prevail in the industry producing the subject goods in terms Para 8(3) of Annexure I of the Rules. The Applicant has claimed that for China, normal value should be determined in accordance with para 7 and 8 of Annexure I of the Rules. The prices or constructed value of the product under consideration in the appropriate market economy third country or the prices from such third country to other countries, including India, has neither been made available by the Applicant nor is this information available with the Authority from any public source. Thus, normal value has been determined on the basis of price paid or payable in India, duly adjusted to include profit, which has been determined considering cost of production in India, after addition for selling, general & administrative expenses and reasonable profits.

b. Normal Value for USA & Korea

9. The Applicant has claimed that the data relating to price in USA and Korea is not available. The Applicant has not provided information regarding the appropriate third country. This information is also not available with the Authority from any public source. The normal value for of USA and Korea has been estimated on the basis of best estimates of cost of production in these countries along with associated selling, general and administrative expenses, and reasonable profit.

c. Export price

10. The Authority has computed the export price for subject goods for the subject countries based on Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) transaction-wise import data. Adjustments have been made for ocean freight, marine insurance, port expenses, bank charges, commission, inland freight expenses (and VAT in case of China PR).

d. Dumping margin

11. The normal value and the export price have been compared at ex-factory level, which prima facie shows dumping margin is above the *de-minimis* level and is significant in respect of the PUC from the subject countries. There is sufficient prima facie evidence that the PUC from subject countries is being dumped into the Indian market by the exporters from the subject countries.

Evidence of injury and causal link

12. Information furnished by the Applicant has been considered for assessment of injury to the domestic industry. The Applicant has furnished evidence regarding the injury resulting from the alleged dumping of dumped imports during the Period of Investigation in the form of increase volume of dumped imports in absolute terms and in relation to production and consumption, price undercutting and price suppressing effect on the domestic industry. The Applicant has claimed that their performance has been adversely impacted resulting in decline in production, capacity utilisation, domestic sales volumes, market share, profitability, cash flow and return on capital employed as a result of increase in imports of product under consideration from subject countries at a price below the selling price, and non-injurious price of the domestic industry. The Applicant has also claimed that there is a further threat of injury to the domestic industry in view of significant capacities of subject goods in subject countries, and suppressing and depressing effect of import prices on domestic selling prices. There is sufficient prima facie evidence of injury being caused to the domestic industry by dumped imports of subject goods from the subject countries.

Initiation of Anti-Dumping Investigation

13. On the basis of the duly substantiated written application by or on behalf of the domestic industry, and having satisfied itself, on the basis of the prima facie evidence submitted by the domestic industry, about dumping of the subject goods originating in or exported from the subject countries, injury to the domestic industry and causal link between such alleged dumping and injury, and in accordance with Section 9A of the Act read with Rule 5 of the Rules, the Authority, hereby, initiates an investigation to determine the existence, degree and effect of any alleged dumping in respect of the subject goods originating in or exported from the subject countries and to recommend the amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

Subject Countries

14. The subject countries for this investigation are China PR, Korea RP and USA.

Period of Investigation (POI)

15. The period of investigation (POI) for the present investigation is 1st April 2019 to 31st March 2020 (12 Months). The injury investigation period will cover the periods 1st April 2016- 31st March 2017, 1st April 2017- 31st March 2018, 1st April 2018- 31st March 2019 and the POI.

Procedure

16. Principles as given in Rule 6 of the Rules will be followed for the present investigation.

Submission of Information

17. In view of the special circumstances arising out of COVID-19 pandemic, all communication should be sent to the Designated Authority via email at email address adg13-dgtr@gov.in and adv12-dgtr@gov.in. It

should be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/ MS Word format and data files are in MS Excel format.

18. The known exporters, their Government through their Embassy in India, the importers and users in India known to be concerned with the subject goods and the domestic industry are being informed separately to enable them to file all the relevant information in the form and manner prescribed within the time-limit set out below.
19. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the form and manner prescribed within the time-limit set out below on the email address mentioned in Para 17 above.
20. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other parties.

Time Limit

21. Any information relating to the present investigation should be sent to the Designated Authority via email at the email addresses adg13-dgtr@gov.in and adv12-dgtr@gov.in within thirty days from the date of receipt of the notice as per Rule 6(4) of the Anti-Dumping Rules. It may, however, be noted that in terms of explanation of the said Rule, the notice calling for information and other documents shall be deemed to have been received within one week from the date on which it was sent by the Designated Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting country. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules.
22. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit.

Submission of information on confidential basis

23. Any party making any confidential submission or providing information on confidential basis before the Authority, is required to simultaneously submit a non-confidential version of the same in terms of Rule 7(2) of the Rules and the Trade Notices issued in this regard. Failure to adhere to the above may lead to rejection of the response / submissions.
24. The parties making any submission (including Appendices/Annexures attached thereto), before the Authority including questionnaire response, are required to file Confidential and Non-Confidential versions separately.
25. The “confidential” or “non-confidential” submissions must be clearly marked as “confidential” or “non-confidential” at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as non-confidential by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect such submissions.
26. The confidential version shall contain all information which is by nature confidential and/or other information which the supplier of such information claims as confidential. For information which are claimed to be confidential by nature or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.
27. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (in case indexation is not feasible) and summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority.
28. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.
29. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without good cause statement on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.
30. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

Inspection of Public File

31. In terms of Rule 6(7) of the Rules, any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties. The modality of maintaining public file in electronic mode is being worked out.

Non-cooperation

32. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

BHUPINDER S. BHALLA, Addl. Secy. & Designated Authority